

रजिस्टर्ड नं० एल० ३३-एस० एम० १३-१४/९८.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, २९ मई, १९९८/८ ज्येष्ठ, १९२०

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-१७१ ००२, २९ मई, १९९८

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) बी (१६)-५/९८. —“दि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन (हिमाचल प्रदेश अधिनियम) ऐक्ट, १९७३ (१९७३ का २३)” के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल

के तारीख 30 अप्रैल, 1998 के प्राधिकार के अधीन एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है। और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1973

(1973 का 23)

(राज्यपाल द्वारा 26-11-97 को अनुमत)

हिमाचल प्रदेश में यथा लघु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत, गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा, निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1973 है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), (जिसे हममें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 1 में "संयुक्त स्टोक कम्पनियों के" शब्दों के स्थान पर "अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाने वाले" शब्द रखे जाएंगे । धारा 1 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के अन्त में आए चिह्न "पूर्ण विराम" के स्थान पर चिह्न "ः" रखा जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:— धारा 3 का संशोधन ।

"परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विशिष्ट सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग को, रजिस्ट्रीकरण फीस के सदाय से छूट दे सकती ।"

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

धारा 4 का संशोधन ।

(क) "संयुक्त स्टोक कम्पनियों के" शब्दों का लोप किया जाएगा ; और

(ख) अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

"यदि कोई सोसाइटी इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है, तो वह पचास रुपए से अधिक जुर्माने की दायी होगी ।"

5. मूल अधिनियम की धारा 12 में, शब्दों "आयुक्त होगा" के पश्चात् शब्द "या जब कभी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी का शासकीय निकाय सोसाइटी के नाम में परिचर्तन करने का विनिश्चय करेगा है," अन्तःस्थापित किए जाएंगे । धारा 12 का संशोधन ।

धारा 12-क
और 12-ख
का अन्तः-
स्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“12-क.—परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण.—(1) जहां नाम में परिवर्तन करने की प्रस्थापना तय पाई गई है और धारा 12 द्वारा विहित रीति में पुष्ट की गई है, वहां ऐसे तय पाई गई और पुष्ट की गई प्रस्थापना की एक प्रति सोसाइटियों के रजिस्ट्रार को, नाम में परिवर्तन करने के रजिस्ट्रीकरण के लिए भेजी जाएगी। यदि प्रस्तावित नाम वही है जिससे कोई अन्य विद्यमान सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई है, या रजिस्ट्रार की राय में ऐसे नाम से इस प्रकार निकट मादृश्य होती है जो जनसाधारण या किसी सोसाइटी के सदस्यों को सम्भाव्यतः प्रवंचित करे, तो रजिस्ट्रार नाम परिवर्तन, रजिस्टर करने से इन्कार कर देगा ।

(2) उप-धारा (1) में उपबन्धित के सिवाए, रजिस्ट्रार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि नाम परिवर्तन करने के बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है, नाम परिवर्तन रजिस्टर करेगा और मामले की परिस्थितियों को पूरा करने के लिए परिवर्तित रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा । ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किए जाने पर नाम परिवर्तन पूर्ण होगा ।

(3) रजिस्ट्रार, उप-धारा (2) के अधीन जारी किए गए प्रमाण-पत्र की किसी प्रति के लिए एक रुपया फीस प्रभारित करेगा और इस प्रकार संदत्त सभी फीस राज्य सरकार के हिसाब में ली जाएगी ।

12-ख.—नाम परिवर्तन का प्रभाव—सोसाइटी का नाम परिवर्तन, सोसाइटी के किन्हीं अधिकारों या बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगा या सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी विधिक कार्यवाही को वृत्तियुक्त नहीं बनाएगा; और कोई विधिक कार्यवाही जो इसके पूर्व नाम से इसके द्वारा या इसके विरुद्ध जारी रखी या प्रारम्भ की जानी थी, इसके नए नाम से इसके द्वारा या विरुद्ध जारी रखी या प्रारम्भ की जा सकेगी ।”

धारा 18 का
संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 18 में, “संयुक्त स्टाक कम्पनियों के” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 19 का
संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 19 में, “दो आने” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस पैसे” शब्द रख जाएंगे ।

नई धारा
21 का

9. मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

अन्तःस्थापन ।

“21. अपराधों का संज्ञान—प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा, न ही किसी

ऐसे अपराध का संज्ञान, रजिस्ट्रार या इस निमित्त लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित परिवाद करने के सिवाय, करेगा।”

10. अनुसूची में वर्णित अधिनियमितियां, उसके चौथे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट विस्तार तक निरसित की जाती हैं।

ऐसे निरसन के होते हुए भी, की गई कोई बात या कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत अनुसूची में वर्णित किन्हीं निरसित अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए या जारी किए गए किसी आदेश, अधिसूचना या नियम भी हैं, इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत होने के विस्तार तक, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई समझी जाएगी।

निरसन और
व्यावृत्तियां।

अनुसूची

(धारा 10 देखिए)

संख्या और वर्ष	अधिनियमितियों का संक्षिप्त नाम	क्षेत्र जहाँ लागू है	निरसन का विस्तार
1	2	3	4
1957 का 31	दो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन (पंजाब अमैण्डमेन्ट) ऐक्ट, 1957	सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश	सम्पूर्ण
1948 का 32	सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (ईस्ट पंजाब अमैण्डमेन्ट) ऐक्ट, 1948	पंजाब - पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में।	सम्पूर्ण
1949 का 6	सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (ईस्ट पंजाब अमैण्डमेन्ट) ऐक्ट, 1949	-यथोपरि-	-यथोपरि-
1961 का 14	सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (पंजाब अमैण्डमेन्ट) ऐक्ट, 1961	-यथोपरि-	-यथोपरि-
1965 का 8	सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (हिमाचल प्रदेश अमैण्डमेन्ट) ऐक्ट, 1965	प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में।	-यथोपरि-